



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 249] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 1985/अग्रहायण 22, 1907
No. 249] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 1985/AGRAHAYANA 22, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1985
संकल्प

फा. सं. 11019/39/85 प्रशा. VII.—भारत सरकार ने प्रायः पर
कराधान के आधार को संशोधित करके व्यय के प्रगामी कराधान की ओर
अग्रसर होने की वाछनायता तथा संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए
वित्तीय विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों तथा प्रशासकों का एक अध्ययन दल गठित
करने का निर्णय किया है ।

2. अध्ययन दल में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. डा. राजा जे० भेल्लैया अध्यक्ष
सदस्य, योजना आयोग
2. डा. अमरेश भागेली सदस्य
निदेशक,
राष्ट्रीय लोक विस्तार तथा नीति संस्थान
3. श्री सी. के. टिक्कू सदस्य
सदस्य (विधायी) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
राजस्व विभाग

4. श्री. पुलिन नायक सदस्य
रीडर
वित्तीय स्कूल आफ इकॉनॉमिक्स

5. श्री पी. ए. नायर सदस्य
अध्यक्ष,
इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आफ इंडिया

6. श्री आर. एन. बारा सदस्य सचिव
वरिष्ठ प्राधिकृत प्रतिनिधि
आयकर अपीलार्थ अधिकरण
नई दिल्ली

3. अध्ययन दल

(i) राजस्व की विवक्षता तथा प्रशासन और अनुपालन की सुविधा
को ध्यान में रखते हुए, व्यष्टियों तथा अल्प गैर निगमित निकायों
के प्रगामी कराधान के लिए व्यय को पूर्ण रूप से या आंशिक
रूप से आधार बनाने की वाछनायता का अध्ययन ;

- (ii) आयकर प्रणाली में इस प्रकार के सुधार के प्रभावों की उसके सभी पहलुओं से, विशेष रूप से निगमित क्षेत्र के कराधान के संबंध में, तथा अन्तर्राष्ट्रीय कर संगतीकरण की समस्याओं की जांच करने;
- (iii) बचतों को शामिल नहीं करने की व्यवस्था करने के लिए यदि आयकर आधार का सुधार वांछनीय तथा व्यवहार्य समझा जाए, तो संक्रमणात्मक समस्याओं के संभावित स्वरूप और परिमाण का जायजा लेना तथा उसका हल सुझाने;
- (iv) संबंधित मामलों की जांच करने का कार्य करेगा।
4. अध्ययन दल का मुख्यालय दिल्ली में होगा। दल अपनी कार्य-विधि स्थगित तैयार करेगा और यथा आवश्यक सूचना मांग सकेगा।
5. राजस्व विभाग समिति के लिए कार्यालय की व्यवस्था करेगा।
6. समिति अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को 31 दिसम्बर 1986 तक प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए और यह कि इसे सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम. एन. तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 13th December, 1985

RESOLUTION

F. No. A-11019/39/85-Ad. VII:—The Government of India have decided to set up a Study Group consisting of fiscal experts, economists and administrators to look into the desirability and feasibility of moving towards progressive taxation of expenditure by modifying the base for income taxation.

2. The Study Group will consist of the following :—

1. Dr. Raja J. Chelliah,
Member, Planning Commission —Chairman
2. Dr. Amaresh Bagchi,
Director,
National Institute of Public Finance
and Policy —Member

3. Shri C. K. Tikku,
Member (Legislation), CBDT,
Department of Revenue —Member
 4. Prof. Pulin Nayak,
Reader,
Delhi School of Economics —Member
 5. Shri P. A. Nair
President, Institute of Chartered
Accountants of India —Member
 6. Shri R. N. Bara,
Sr. Authorised Representative,
Income-tax Appellate Tribunal,
New Delhi. —Member- Secretary
3. The Study Group will
- (i) study the desirability of moving towards expenditure, wholly or partly, as the base for progressive taxation of individuals and other non-corporate entities, keeping in view the constraint of revenue and ease of administration and compliance;
 - (ii) examine the implications of such reform of the Income-tax system in all its aspects particularly in relation to taxation of the corporate sector and problems of international tax harmonisation;
 - (iii) assess the likely nature and magnitude of transitional problems and suggest solutions, in case reform of the Income-tax base to provide for exclusion of savings is considered desirable and feasible, and
 - (iv) examine related issues.
4. The headquarters of the Study Group will be at Delhi. The Group will devise its own procedure and may call such information as it considers necessary.
5. The Department of Revenue will provide the Secretariat for the Committee.
6. The Committee will submit its report to the Finance Minister by the 31st December, 1986.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

M. N. TIWARY, Jr. Secy.